

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 9 अक्टूबर, 2023 आश्विन 17, 1945 शक सम्वत

> उत्तर प्रदेश शासन विकित्सा अनुभाग-5

संख्या 194 / पाँच—5-2023 लखनऊ, 9 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

प0आ0-484

चूँिक सेवाएं या प्रसुविधायें या सहायकी प्रदान करने के एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएं सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिये बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुये सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;

और, चूँिक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे ''विभाग'' कहा गया है) नीचे सारणी में उल्लिखित स्कीमों (जिसे आगे स्कीम कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है :--

क्रम-संख्या	स्कीम का नाम
1	ए०ई०एस० / जे०ई० रोग के मृतकों एवं दिव्यांगों के परिजनों को आर्थिक सहायता

जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश (जिसे आगे "क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण" कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है;

और, चूँिक, पूर्वोक्त स्कीम के अधीन क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार समस्त श्रेणी के एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (ए०ई०एस०)/जापानी इंसेफेलाइटिस (जे०ई०) के कारण मृतक और दिव्यांग इत्यादि (जिन्हे आगे "लाभार्थी" कहा गया है) को वित्तीय सहायता (जिसे आगे "प्रसुविधा" कहा गया है) के रूप में सहायता दी जाती है;

और, चूँिक, पूर्वोक्त स्कीम में उपगत आवर्ती व्यय और उत्तर प्रदेश की संचित निधि अंतर्गस्त है :-

अतएव, अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकीयों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश सरकार एतदृद्ववारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- 1—(1) उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यक्ति को आधार अधिप्रमाणन से गुजरने के लिए एतद्द्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।
- (2) उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या, जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त स्कीम को रजिस्ट्रीकृत करने के पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी:

परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करनें का हकदार हो और ऐसे व्यक्तियों को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिये किसी आधार नामांकन केंद्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची| पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग के लिए अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों, और यदि अपने-अपने ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित न हो, तो विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई०डी०ए०आई०) के विद्यमान रिजस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रिजस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को आधार समनुदेशित किये जाने के समय तक, उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधायें ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन दी जायेंगी, अर्थात् :—

- (क) यदि उसने नामांकन किया हो तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक; अर्थात् :--
 - (एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या
 - (दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
 - (तीन) पासपोर्ट; या
 - (चार) राशन कार्ड; या
 - (पाँच) मतदाता पहचान पत्र; या
 - (छः) मनरेगा कार्ड; या
 - (सात) किसान फोटो पासबुक; या
 - (आठ) मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस; या
 - (नौ) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा अपने शासकीय शीर्षनामा पर जारी किये गये ऐसे व्यक्ति की फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र; या
 - (दस) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2—पूर्वोक्त स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान कराने के उद्देश्य से, विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करनें के लिये समस्त अपेक्षित व्यवस्थायें करनी होंगी कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार, उन्हें पूर्वोक्त अपेक्षाओं से अवगत कराने के लिए किया जाये।

3—समस्त मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे; अर्थात :–

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली (आई०आर०आई०एस०) स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनायी जाएगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधायें प्रदान करनें के लिए फिंगरप्रिंट

अधिप्रमाणन के साथ ही साथ एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली (आई०आर०आई०एस०) स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

- (ख) यदि फिंगरप्रिंट या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली (आई०आर०आई०एस०) स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, जहाँ कहीं सम्भाव्य और अनुज्ञेय हो, सीमित समय की विधिमान्यता के साथ, यथास्थिति, आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वनटाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जा सकता है;
- (ग) अन्य समस्त मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव न हो, वहाँ उक्त स्कीम के अधीन प्रसुविधायें, ऐसे भौतिक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं और क्विक रिस्पांस कोड (क्यू०आर०कोड) रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी। 4—उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के उददेश्य से कि उक्त स्कीम के अधीन कोई वास्तविक

म=0परावर के जारास्वर, यह चुनारवर करने के उपरान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से डी०बी०टी० मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या डी० 26011/04/2017डी०बी०टी०, दिनांक 19 दिसंबर, 2017 में यथारेखांकित अपवाद हैण्डलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

5-यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से, पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 194/Five-5-2023, dated October 9, 2023.

No. 194/Five-5-2023

Dated Lucknow; October 9, 2023

WHEREAS the use of Aadhar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

AND, WHEREAS, the Department of Medical Health and Family Welfare, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "Department") is administering the Scheme (hereinafter referred to as the "Scheme") mentioned in the table below:-

Sl. no.	Name of Schemes
1	Financial assistance to the relatives of the dead and disabled of AES/JE disease

Which is being implemented through the Department of Medical Health and Family Welfare, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the "Implementing Agency");

AND, WHEREAS, under the aforesaid Scheme assistance is given in the form financial assistances (hereinafter referred to as the "benefit") to the deceased and handicapped due to Acute Encephalitis Syndrome (AES)/Japanese Encephalitis (JE) of all category, *etc.* (hereinafter referred to as the "beneficiaries") by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

AND, WHEREAS, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred and Consolidated Fund of Uttar Pradesh;

Now, Therefore, in the pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act") the Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following, namely:-

- 1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number to undergo Aadhaar authentication;
- (2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhar enrolment before registering for the Scheme:

Provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment Centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 the Department through its Implementing Agency is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with existing Registrars of UIDAI/or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to production of the following documents, namely:-

- (a) if he enrolled, his Aadhaar enrolment identification slip; and
- (b) any of the following documents, namely:-
 - (i) Bank or post office Passbook with photo; or
 - (ii) Permanent Account Number (PAN) card; or
 - (iii) Passport; or
 - (iv) Ration Card; or
 - (v) Voter Identity Card; or
 - (vi) MGNREGA Card; or
 - (vii) Kisan Photo Passbook; or
- (viii) Driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988); or
- (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a *Gazetted* officer or a Tehsildar on an official letterhead; or
 - (x) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specially designated by the Department for the said purpose.

- 2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the aforesaid requirements.
- 3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometric of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted namely:-
 - (a) In case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication. Thereby, the Department through its Implementing Agency shall make provision for Integrated Risk Information System (IRIS) scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
 - (b) In case the biometric authentication through fingerprints or Integrated Risk Information System (IRIS) scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
 - (c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response Code (QR Code) reader shall be provided at convenient location by the Department through its Implementing Agency.

- 4. In addition to the above, in order to ensure that no *bonafide* beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December, 2017.
 - 5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official *Gazette*.

By order,
PARTHA SARTHI SEN SHARMA,
Pramukh Sachiv.